बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक विकास पर बल

–ओ.पी. शर्मा

बजट आर्थिक विकास की नीति के साथ अर्थव्यवस्था की दिशा भी निर्धारित करता है। एक प्रकार से बजट अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। इस हिसाब से यह देखा जाना चाहिए कि इस बजट में आर्थिक समस्याओं पर समाधान के क्या कदम उठाए गए हैं? इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में जो कमजोर आर्थिक घटक हैं, उन्हें सुधारने के क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी, 2015 को केन्द्रीय बजट 2015–16 लोकसभा में पेश किया। जेटली द्वारा पेश किया गया यह इस वित्तवर्ष का पूर्णकालिक बजट है। इससे पहले उन्होंने जुलाई माह में वित्तवर्ष 2014–15 का बजट पेश किया था। ताजे आर्थिक सर्वेक्षण पर नजर डाले तो अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने लगा है। जीडीपी वृद्धि दर 2011–12 आधार वर्ष के अनुसार 2014–15 में 7.4 प्रतिशत हो गई है। इसके 2015–16 में 8.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। हालांकि दुनिया में मंदी का माहौल है किंतु भारत में जीडीपी वृद्धि को दो अंकों में पहुंचाने का वातावरण तैयार किया जा रहा है। अगर भारत की जीडीपी वृद्धि दहाई अंक को पार कर जाती है तो गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बड़ी सीमा तक कम हो सकेगी। भारत के पास 340 बिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भंडार है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। रुपया मजबूत है और महंगाई काबू में है। पिछले वर्षों में विदेशी व्यापार पर मंदी का असर था। वित्तवर्ष 2012–13 में निर्यात वृद्धि और 2013–14 में आयात वृद्धि दर ऋणात्मक थी। अप्रैल–दिसम्बर 2014–15 में विदेशी व्यापार की स्थिति सुधरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ऐतिहासिक घटी इससे भारत में वित्तीय अनुशासन की स्थिति बनी। चालू खाता घाटा भी कम हुआ है। सेंसेक्स ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। भारत के महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचकों के सुधरने से विदेशी निवेशकों का दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति अनुकूल होगा।

आर्थिक चुनौतियां

अच्छे दिन दिखाने के आर्थिक सूचकों के बीच कई आर्थिक समस्याएं ऐसी हैं जो अर्थव्यवस्था में मुंह बाएं खड़ी हैं। आर्थिक विषमता मुखर समस्या है। धनी और गरीब के बीच खाई को पाटा नहीं जा सका है। धनी बहुत अधिक धनी हुआ है और गरीब की आय अपेक्षित नहीं बढ़ी है। आर्थिक विषमता का कारण क्षेत्रीय विषमता भी है। भारत के कई राज्य विकास के मामले में पीछे हैं। क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास में पिछड़ने से लोग आर्थिक विषमता से

ग्रसित होते हैं। भारत विश्व का युवा देश है। यहां की आबादी में युवा अधिक हैं किंतु ग्रामीण आबादी अधिक है। गांवों में युवा बड़ी संख्या में हैं। आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका घटने से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर घट गए हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी मुखर हो गई है। भारत आर्थिक विकास में तो तीव्रता से बढ़ रहा है किंतु सामाजिक विकास स्थिति में कमजोर है।

भारत ने विगत वर्षों में आर्थिक प्रगति तो की किंतु वैश्विक आर्थिक सूचकों में भारत की स्थिति उत्साहवर्द्धक नहीं है। विश्व के कुल विदेश व्यापार में भारत का भाग अभी भी बहुत कम है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी अधिक आकर्षित नहीं किया जा सका है। बढ़ता विदेशी ऋण अधिक विदेशी मुद्रा भण्डार की महत्ता को घटा देता है। भारत की अर्थव्यवस्था समानांतर अर्थव्यवस्था के घेरे में है। काली अर्थव्यवस्था के चलते प्रासंगिक आर्थिक नीतियां प्रभावी भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पाती हैं। भारत ढाई दशकों से आर्थिक उदारीकरण के मार्ग पर है। अर्थव्यवस्था में भारी संरचनात्मक बदलाव किए जा चुके हैं। आर्थिक सुधारों की गति अभी भी जारी है। इस दौर में आर्थिक सुधारों से आर्थिक समस्याओं के समाधान के प्रयत्न किए गए हैं।

विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अर्थव्यवस्था में मौजूद समस्याओं के समाधान आवश्यक हैं। बजट आर्थिक विकास की नीति के साथ अर्थव्यवस्था की दिशा भी निर्धारित करता है। एक प्रकार से बजट अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। इस हिसाब से यह देखा जाना चाहिए कि इस बजट में आर्थिक समस्याओं पर समाधान के क्या कदम उठाए गए हैं? इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15 में जो कमजोर आर्थिक घटक हैं, उन्हें सुधारने के क्या कदम उठाए गए हैं?

बुनियादी सुविधाओं पर जोर

वित्तवर्ष 2014–15 में प्रधानमंत्री जन–धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, पारदर्शी कोयला नीलामी आदि रेखांकित की जाने वाली उपलब्धियां हैं। जहां जन–धन योजना में करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए वहीं स्वच्छ भारत अभियान को आंदोलन की तरह क्रियान्वित किया गया। जन–धन योजना के निर्धारित लक्ष्य नियत समय में पूरे कर लिए गए। बजट में इन योजनाओं को और अधिक मजबूती प्रदान की गई है। बजट की महत्वपूर्ण बात देशवासियों को बुनियादी सुविधाओं पर अधिक बल देना है। वर्ष 2022 तक सबके लिए घर, हर घर में शौचालय और सब घरों में बिजली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे बड़ी बात 2022 तक गरीबी खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित करना है। गांव और शहर के बीच भेद खत्म करने की बात कही गई है। गांव और शहर में एक जैसी संचार सुविधा का विकास किया जाएगा। हर गांव में मेडिकल सुविधा होगी। ज्यादा स्कूल खुलेंगे। हर पांच किलोमीटर के दायरे में सीनियर सेकेण्डरी स्कूल होगा। ये सब ऐसे कदम हैं अगर वे लागू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से देशवासियों को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे।

गांवों की सुध

बजट में गांवों की दशा सुधारने की कारगर पहल है। सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2022 तक गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य है। इसके अलावा गांवों के विकास की योजनाओं में आवंटन बढ़ाया गया है। कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का आकार 33 करोड़ रुपये से छह गुना बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना की घोषणा की गई है। सिंचाई योजना के लिए 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए 3500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। किसानों को कृषि ऋण के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गांवों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 2022 तक रोजगार की बात कही गई है। मनरेगा के लिए 34699 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में मत्स्य क्रांति पर बल है। देसी और समुद्री मत्स्य पालन के लिए बजट दस गुना बढ़ाकर 411 करोड़ रुपये किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

बजट में आम लोगों की सामाजिक सुरक्षा की प्रासंगिक पहल की गई है। गरीबों के लिए नई बीमा योजनाओं की शुरुआत हुई है। जन–धन योजना वालों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना में मात्र 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के दुर्घटना–मृत्यु जोखिम को कवर किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की घोषणा की गई है। इसके अर्न्तगत 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए एक रुपये प्रतिदिन के प्रीमियम पर दुर्घटना, मृत्यु जोखिम पर दो लाख रुपये तक का कवर दिया जाएगा। साठ साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें एक हजार रुपये सरकार देगी और एक हजार रुपये व्यक्ति को देना होगा। साठ साल की उम्र के बाद अगले पांच वर्ष तक सरकार एक हजार रुपये देगी। भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति कमजोर है। बहुत कम लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं। जनाधिक्य का एक कारण सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी है। बजट में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में की गई पहल से बड़ी आबादी के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने की संभावना है।

मेक इन इण्डिया को गति

केन्द्र सरकार मेक इन इण्डिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रयत्नशील है। विनिर्माण और निवेश ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत को विश्व में आर्थिक ताकत के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में भारत की विशिष्ट पहचान बन चुकी है। विश्व अर्थव्यवस्था के मंदी से उभरने के बाद सेवा क्षेत्र फिर से जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाने में भूमिका निभाएगा। कृषि में भारत के खाद्यशक्ति के रूप में उभरने की क्षमता है। केन्द्र सरकार ने 2014–15 से मेक इन इण्डिया की शुरुआत की है। बजट में मेक इन इण्डिया को गति देने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। उद्योगों को बढ़ाने के लिए कारपोरेट टेक्स अगले पांच वर्षों के दौरान 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। इससे निवेश के विकास और अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। कर की दर कम होने से उत्पादन लागत में कमी होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 20000 करोड़ रुपये के निवेश व अवसंरचना निधि की स्थापना की गई है। मेट्रो परियोजनाओं के लिए 8260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश वृद्धि के लिए टैक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड की घोषणा की गई है। आवास व शहरी विकास के लिए 22407 करोड़ रुपये, सड़कों के लिए 14031 करोड़ रुपये, रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 10050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रोजगार सृजन

उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से रोजगार अवसर सृजित होंगे। भारत में युवा शक्ति अधिक है, उन्हें रोजगार की अधिक दरकार है। देश में रोजगार मांगने वालों की तादाद हर साल 2.3 प्रतिशत से बढ़ रही है जबकि रोजगार में केवल 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। भारत में 2022 तक बेरोजगारी समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोजगार वृद्धि के लिए 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इण्डिया' में समन्वय के प्रयत्न किए गए हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग को 1000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ग्रामीण छात्रों में रोजगारपरक योग्यता का विकास करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल उन्न्यन योजना लाई गई है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) तंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। मेक इन इण्डिया अभियान से भारत के लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों के सृजन हेतु वैश्विक विनिर्माण केन्द्र विकसित किया जाएगा।

कालाधन पर मार

कालाधन बड़ी समस्या है। इसने अर्थतंत्र की जड़ें खोखली कर रखी हैं। इसे निकालने की कोशिश की गई किंतु यह घटने के स्थान पर बढ़ता ही गया। पिछले वर्षों से यह ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। बजट में देश के भीतर और विदेश में जमा कालाधन पर मार की गई है। आय और सम्पत्ति छुपाने तथा विदेशी सम्पत्ति के संबंध में कर वंचना के लिए 10 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। कालाधन के अपराधों को संगीन अपराध माना जाएगा और ऐसे अपराधी के लिए आय और सम्पत्ति की मौजूदा दर से 300 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार कालाधन पर बिल लाएगी। बेनामी लेन–देन विधेयक भी पेश होगा। नये विधेयक में आयकर विवरणी दाखिल करने और अधूरी जानकारी के दाखिल करने पर 7 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान होगा। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों के मामले में इस विधेयक के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी। फेमा 1999 और धनशोधन कानून 2002 में बदलाव होगा। एक लाख से अधिक की खरीद और बिक्री के लिए पेन अनिवार्य कर दिया गया है। 20 हजार से अधिक के लेन–देन नकद किए जाने पर रोक लगा दी गई है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से व्यापार पर जोर दिया गया है। सरकार जल्दी ही गोल्ड बॉण्ड लांच करेगी। इन पर निश्चित ब्याज मिलेगा। इसके अलावा भारत की छाप वाले स्वर्ण सिक्के जल्दी ही बाजार में आएंगे। अगर कालाधन पर अकुंश लगता है या निकलता है तो इससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। कालाधन के खत्म होने से आर्थिक नीतियां विकास दर को बढ़ाने में अधिक सहायक होंगी। देश में अपराधवृत्ति है चाहे यह धन्ना सेठों के करचोरी व मिलावट के रूप में हो या फिर लोगों द्वारा किए गए अपराध। इनकी पुष्टि आयकर छापे और पुलिस विभाग द्वारा जारी अपराध आंकड़ों से होती है।

कड़े कदम

बजट में सर्विस टैक्स 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। इससे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2 प्रतिशत सेस तय किया गया है। सभी टैक्स वाली सुविधाओं पर यह सेस लगेगा। अमीरों से वेल्थ टैक्स

हटा दिया गया है किंतु एक करोड़ रुपये से अधिक कर योग्य आय वाले धनिकों पर 2 प्रतिशत का सरचार्ज लगा दिया गया है। आय कर की दर और स्लेब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि टैक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड की घोषणा की गई है। हेल्थ इंश्योरेंस पर 80डी में छूट 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें भी 30000 रुपये की कटौती मिलेगी। गंभीर बीमारी पर खर्च के लिए 60000 रुपये की कटौती सीमा बढ़ाकर 80000 रुपये कर दी गई है। आश्रित विकलांग व्यक्ति के इलाज के लिए कटौती सीमा 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी गई है। गंभीर विकलांगता की दशा में कटौती सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। परिवहन भत्ते पर मासिक कर छूट 800 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दी गई है। वेतनभोगी वर्ग को आयकर में राहत दी गई है, इस राहत का मार्ग खपत केन्द्रित नहीं बचत केन्द्रित है।

प्रासंगिक पहल

बजट में बेटियों और महिलाओं के बचाव व सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बेटियों की सुरक्षा और विवाह के लिए सुरक्षित निवेश आवश्यक है। बेटियों के भविष्य को सुकन्या समृद्धि योजना से सुरक्षित और लाभकारी बनाया गया है। इसमें व्यक्ति के निवेश के साथ सरकार भी सहयोग देगी। इसमें निवेश से करों में राहत तो मिलेगी ही, साथ ही मिलने वाला ब्याज करमुक्त रखा गया है। देश की आधी आबादी सुरक्षित रहे, इसके लिए महिलाओं के बचाव, सुरक्षा, जागरुकता, महिलाओं की पैरवी के कार्यक्रमों के लिए निर्भया फण्ड में 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

अर्थव्यवस्था पर सब्सिडी का बड़ा बोझ है। सब्सिडी को कम तो नहीं किया गया है किंतु इसके सदुपयोग के कदम उठाए गए हैं। सब्सिड़ी के लिए 'जाम' अर्थात जन–धन योजना, आधार और मोबाइल की शुरुआत की गई है। 20 हजार करोड़ रुपये की पूंजी और तीन हजार करोड़ रुपये की गारण्टी मनी के साथ एमएसएमई के लिए 'मुद्रा बैंक' (माइक्रो यूनिट डवलपमेंट एण्ड रिफाइनेंस एजेंसी) की घोषणा की गई है। मुद्रा बैंक उन उद्यमियों की वित्तीय जरूरतें पूरी करेगा जो अभी बहुत ऊंची दरों पर उधारी लेते हैं। इस बैंक से स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

बजट में उच्च शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल इण्डिया, महिला उद्यमिता, खेल प्रशिक्षण आदि के विकास की कारगर पहल की गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू और आन्ध्र प्रदेश में आईआईएम, कर्नाटक में आईआईटी और आईएमएस धनबाद को पूर्ण आईआईटी का दर्जा, पांच राज्यों जम्मू–कश्मीर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम में एम्स खुलेंगे और राजस्थान, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में नेशनल फार्मा इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम को तीव्र गति देने के लिए नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पूरे देश में फैलाया जाएगा। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 'नई मंजिल' योजना के लिए 3738 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में 'ई–बिज' की घोषणा की गई है। इसमें नये व्यापार के लिए आवश्यक सभी जानकारी एक वेबपोर्टल पर होगी। केन्द्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग की ओर से ई–बिज वेबपोर्टल का उद्देश्य व्यापार करना आसान बनाने के मामले में विश्व में भारत की रैंकिंग में सुधार करना है।

दृष्टिकोण

विश्व अर्थव्यवस्था भले ही मंदी से उभर नहीं सकी हो किंतु भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से दौड़ती दिख रही है। भारत दहाई अंक की विकास दर अर्जित करने की स्थिति में है किंतु सामाजिक विकास की स्थिति ने आर्थिक विकास को प्रभावित कर रखा है। इस बजट का मजबूत पक्ष बुनियादी सुविधाओं का विकास है। 2022 तक सबको घर, हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, हर गांव में सड़क, हर गांव में चिकित्सा सुविधा, हर घर में एक को रोजगार, गरीबी खत्म का स्वप्न संजोया गया है। इन स्वप्नों के साकार होते ही भारत विकसित देशों की श्रेणी में होगा। बजट में सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने की कारगर पहल है। 'मेक इन इण्डिया' और 'स्वच्छ भारत' अभियान नई सरकार के दो ऐसे नए कदम हैं जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा दे सकते हैं। मगर इन योजनाओं की सफलता के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। एक बार आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास गति पकड़ ले तो भारत विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा। आर्थिक उदारीकरण के पच्चीस सालों में सेवा क्षेत्र पर बल रहा और ग्रामीण विकास को भी साथ लेकर चला गया किंतु उद्योग और विनिर्माण पिछड़ गया। 'मेक इन इण्डिया' में विनिर्माण पर भारी बल है। इसके साथ केन्द्र सरकार बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दे रही है। उम्मीद है कि केन्द्र सरकार की बजट में की गई नई पहल 'लोगों के अच्छे दिन' में चरितार्थ होगी।

विभागाध्यक्ष, आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबंध विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सवाई माधोपुर (राजस्थान)
ई–मेल : opsomdeep@yahoo.com